International Journal of Applied Research 2022; 8(2): 12-15

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(2): 12-15
www.allresearchjournal.com
Received: 07-12-2021
Accepted: 09-01-2022

डॉ. विधि शर्मा
सोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
डॉ. विधि शर्मा
सोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली, भारत

आपदा प्रबन्धन: एक मूल्यांकन

डॉ. विधि शर्मा

प्रस्तावना

ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे किसी समुदाय अथवा समाज की कार्य-प्रणाली गंभीर रूप से बाधित हो तथा जिसमें मनुष्य के जीवन, सामग्री, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को हानि पहुंचे, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। इन आपदाओं को ईश्वर का प्रकोप भी कहा जाता है। आज भले ही मनुष्य ने हर क्षेत्र में बहुत विकास कर लिया है, चाहें विज्ञान की बात करें या तकनीक की, सभी में प्रगति के नए आयाम मानव छू रहा है। पर विकास की इस अन्धी दौड़ में उसने प्रकृति के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। वह इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि प्रकृति का बेतहाशा शोषण करने में संलिप्त है चाहें नदी हो या पहाड़, जंगल हो या मैदान वह बस अपना फायदा सोच रहा है। उसकी इस आत्मकेन्द्रित सोच का ही यह नतीजा है कि प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है और असंतुलन की यह स्थिति ही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे रही है; जैसे - भूकम्प, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, दावानल, हिमखण्डों का पिघलना, बवंडर आदि। इन आपदाओं से मनुष्य की प्रगति बाधित होती है और जान - माल की भारी हानि उठानी पड़ती है। भारत में सन 2000 से 2020 के बीच तीन बड़े भूकम्प, एक बार सुनामी, दो बार भूस्खलन, एक बार भीषण दावानल, कई बार बवंडर एवं चक्रवाती तूफान आ चुके हैं और सूखे का सामना तो अक्सर ही देश के कई राज्यों को करना पड़ा है। इन सभी आपदाओं से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है और देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी पहुंची है। पिछले 20 सालों (2000 से 2020) में भारत में आई कुछ आपदाएं जिन्होंने आपना दूरगामी प्रभाव छोड़ा इस प्रकार हैं (1) :

वर्ष	राज्य	प्राकृतिक आपदा	प्रभाव
2001	गुजरात	भूकम्प	25,000 लोगों की मौत लगभग 65 लाख लोग प्रभावित
2004	दक्षिण भारत	सुनामी	5,640 लोग लापता लगभग 21 लाख लोग प्रभावित
2005	कोसी, बिहार	बाढ़	527 लोगों की मौत लगभग 33 लाख लोग प्रभावित
2005	कश्मीर	भूकम्प	1,350 लोगों की मौत 6,268 लोग घायल, हजारों बेघर
2006	सूरत, गुजरात	बाढ़	लगभग 150 लोगों की मौत
2013	उत्तराखण्ड	भूस्खलन एवं बाढ़	6,054 लोगों की मौत्
2014	कश्मीर	बाढ़	2,550 गांव प्रभावित
2016	उत्तराखण्ड	दावानल	7 लोगों की मौत 11,214 एकड़ के इलाके में

इन प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ मानव जनित आपदाएं भी हैं (हालांकि इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी काफी हद तक मनुष्य ही जिम्मेदार है, चाहें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही) जैसे - साम्प्रदायिक दंगे, आगजनी, आतंकवाद, विस्फोट, दुर्घटनाएं आदि।

वैश्विक स्तर पर इन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर किए जाने वाले प्रयास को ही आपदा प्रबन्धन कहा जाता है। "आपदा प्रबन्धन को आपदाओं के प्रभाव को कम करने तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिम्मेदारियों एवं संसाधनों के संगठन और प्रबन्धन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है"।(2) धैर्य, विवेक, साहस, परस्पर सहयोग की भावना एवं उचित प्रबन्धन द्वारा ही इन आपदाओं से पार पाया जा सकता है। आपदा प्रबन्धन दो प्रकार से किया जाता है - 1. आपदा से पूर्व 2. आपदा के पश्चात। आपदा पूर्व प्रबन्धन को जोखिम प्रबन्धन भी कहा जाता है। आपदा के जोखिम उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं जो मौसम और समय के साथ बदलते रहते हैं। आपदा पूर्व प्रबन्धन के तीन अंग हैं : 1.जोखिम की पहचान, 2. जोखिम में कमी 3.जोखिम का स्थानांतरण। किसी भी आपदा के लिए रणनीति बनाते समय पहला चरण है जोखिम की पहचान कर पाना जो प्राकृतिक वातावरण की जानकारी पर निर्भर करती है। जोखिम की पहचान के पश्चात हर संभव प्रयास किया जाता है कि नुकसान कम से कम हो; जैसे बाढ़, तूफान, चक्रवात आदि की पूर्व सूचना रेडियो आदि संचार के व्यापक एवं सशक्त माध्यम द्वारा जनता तक पहुंचाई जा सकती है, प्रभावित इलाकों को पहले से खाली करवाया जा सकता है। "इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य और जिला स्तर पर समितियों, संस्थानों का गठन किया गया है जो आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाते हैं"। (3) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA), नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), केन्द्रीय जल आयोग (CWC) जैसे संगठन न केवल आपदाओं के दौरान अथक रूप से कार्य करते हैं बल्कि इनसे संबन्धित शोध भी करते हैं जिसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलते हैं|

आपदा की पूर्व तैयारी का महत्व : आज विश्व के हर कोने में किसी भी समय में आपदाओं का प्रकोप देखा जा सकता है। इन आपदाओं के दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की, प्रभावित लोगों तक चिकित्सकीय सहायता, खाना, रहने की जगह तथा अन्य आवश्यक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक और अनपेक्षित रूप से आती हैं। उस समय इनसे निपटने की तैयारी का समय बहुत कम मिल पाता है या मिलता ही नहीं। इसीलिए यह बहुत जरूरी

है कि किसी भी तरह की आपदा से पूर्व ही उसके लिए योजना बनाने का कार्य और अन्य तैयारी कर ली जाए। आपदा के लिए तैयारी का अर्थ है आपदा के प्रभाव की तीक्ष्णता को कम करने के लिए बचाव के तरीके अपनाना। इसका मुख्य लक्ष्य है आपदा के दायरे में आने वाली जनसंख्या पर आपदा के प्रभाव को घटाना। इसका उद्देश्य होता है ऐसी सहयोगी योजना का निर्माण करना जिसमें साधन, समय तथा प्रयास का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके। आपदा की तैयारी में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा जान-माल के नुकसान को बचा सके। साथ ही उसका यह भी लक्ष्य होता है कि वह प्रभावित लोगों को शीघ्र अति शीघ्र सामान्य स्थिति में ला सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में उसके लिए की गई पूर्व तैयारी बहुत मायने रखती है। साथ ही जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही अपेक्षित है। किसी भी बड़ी आपदा के घटित होने के 24 घण्टों के अंदर-अंदर मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है अन्यथा आपदा से मरने एवं घायल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है। सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं। बहुत से संस्थानों एवं संगठनों का गठन किया गया है ताकि समय पर हताहत लोगों तक मदद पहुंच सके। लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सच है कि लोगों में इस जानकारी को लेकर जागरूकता का अभाव है या यों कहें की उन तक इस सन्दर्भ में विज्ञापन तथा अन्य संचार माध्यमों से सूचना पहुंचाने का कार्य सुचारु रूप से नहीं किया गया है। आग लगने अथवा मकान गिरने आदि की स्थिति में ही लोगों को यह पता है कि फायर सर्विस की मदद ली जा सकती है। एन.जी.ओ. और मैडिकल टीम की भी आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। यहां तक कि किसी भी आपदा के समय पुलिस की मदद भी ली जा सकती इस बारे में भी लोगों के पास समुचित जानकारी का अभाव है। वह पुलिस की भूमिका चोरी, हत्या, दुर्घटना आदि जैसी स्थितियों तक ही सीमित मानते हैं।

यदि हम भारतीय परिवारों की बात करें तो उसमें महिलाओं की भूमिका केन्द्रीय होती है। सर्वेक्षण से भी यह प्रमाणित हुआ है कि परिवार में सबसे अधिक समय महिलाएं ही बिताती हैं और परिवार में लिए जाने वाले निर्णय में भी उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षित परिवारों की महिलाओं में भी आपदा प्रबन्धन को लेकर सजगता नहीं दिखती। न तो उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन को लेकर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के नाम पता हैं और न ही उनका घर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थित के लिए तैयार है। लगभग 95% लोगों के पास आपदा प्रबन्धन किट (Family Disaster Management Kit) भी उपलब्ध नहीं है। (4)

भारत जैसे विशाल एवं प्राकृतिक रूप से समृद्ध देश की बात की जाए तो यहां आरंभ से ही प्राकृतिक आपदाएं लोगों के लिए चुनौती बनकर सामने आती रही हैं। चाहें हम कितने भी विकसित और साधन संपन्न क्षेत्रों के नागरिकों की बात करें सभी ने अपने जीवन में कभी-न-कभी इन प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। और यदि स्वयं नहीं भी झेला तो उनके परिवार के किसी-न-किसी सदस्य ने इन आपदाओं के विकराल रूप को अवश्य देखा है, उनका सामना किया है। "उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 90% लोगों के परिवार के सदस्यों ने भूकम्प, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेला है।" (5) लेकिन फिर भी उनके पास आपदा प्रबन्धन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई भी ट्रेनिंग या दक्षता हासिल नहीं है, जिससे वह इन आपात स्थितियों के लिए स्वयं को तैयार

कर सकें। कुछ छात्राओं द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह अवश्य पता चला है कि महाविद्यालय के स्तर पर उन्हें मॉक ड्रिल द्वारा इस क्षेत्र में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई है लेकिन इसे व्यवस्थित ट्रेनिंग नहीं कहा जा सकता। पर शत-प्रतिशत लोग इस तरह की आपदा प्रबन्धन से संबन्धित किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पाने की इच्छा रखते हैं।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि आपदाओं से बचा नहीं जा सकता लेकिन हम उनके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। इसके लिए नई तकनीकों की जानकारी तथा ट्रेनिंग एवं सजगता की आवश्यकता है जिससे आपदा की स्थिति में होने वाले प्रकृति, पशु, लोगों के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इस सन्दर्भ में जनता तक जानकारी पहुंचाना भी उनका दायित्व है ताकि उनको जागरूक किया जा सके। इसके लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जा सकता है तथा संचार माध्यमों की मदद से भी जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है।" रेडियो संचार का सशक्त माध्यम है जिसकी पहुंच समस्त भौगोलिक क्षेत्र तथा शत-प्रतिशत जनता तक है। अत: रेडियो कार्यक्रम की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है"। (6) साथ ही हम यह कह सकते हैं कि देश का युवा वर्ग यदि आपदाओं और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेगा तो स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए स्कूल एवं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्रों के लिए ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि भारतीय परिवारों में स्त्रियों की केन्द्रीय भूमिका रही है, इस बात का भी खयाल रखते हुए उनकी ट्रेनिंग पर विशेष बल होना चाहिए। यदि हम आपदा प्रबन्धन के लिए युवाओं को तैयार करेंगे तो वह आगे अपने परिवार तथा मित्रों के बीच इससे संबन्धित जानकारी को साझा करके इस नेटवर्क को बहुतायत जनता तक पहुंचा पाएंगे और हमारा देश किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहेगा।

सन्दर्भ

1. http://www.drishtiias.com
2. http://www.physio.pedia.com
3. http://ndma.gov.in
4. http://www.ifrc.org
5. http://en.wikipedia.org
6. http://www.physio.pedia.com